



www.agrabharat.in

नई सोच का अखबार



दैनिक हिन्दी समाचार पत्र

वर्ष: 19

अंक: 119

आगरा, शनिवार 17 अक्टूबर 2026

पृष्ठ: 8 मूल्य: 2.00 ₹.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर किया पलटवार : लोकतंत्र अराजकता फैलाने का लाइसेंस नहीं

नई दिल्ली, (ए)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों के विरोध-प्रदर्शनों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र अराजकता फैलाने या देश के विकास में बाधा डालने का लाइसेंस नहीं है। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर युवाओं की ऊर्जा को अराजकता की ओर मोड़ने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में टकराव के बजाय संवाद का रास्ता अपनाया जाना चाहिए और जनमत का सम्मान करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ ने दिल्ली में हालिया विरोध-प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तथा मुख्य चुनाव आयुक्त फैलावे के जरिए देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन की चर्चा को भी विपक्ष का निंदनीय प्रयास बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट



की टिप्पणियों पर भी गौर करना चाहिए और अपनी राजनीतिक भूमिका की समीक्षा करनी चाहिए।

कांग्रेस के शासनकाल पर उठाए सवाल

रक्षा मंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल की तीन घटनाओं का उल्लेख करते हुए आपातकाल, 1984 के सिख-विरोधी दंगों और 1990 में रामभक्तों पर गोली चलाने की घटना को लेकर

पाटी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को कमजोर किया गया। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर संविधान का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को प्रभावित किया गया था। उन्होंने 1993 में चुनाव आयोग में दो

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से नवीन चावला को हटाने की मांग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर चुनाव आयोग को अपने प्रभाव में रखने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि, ये आरोप रक्षा मंत्री के राजनीतिक वक्तव्य का हिस्सा हैं।

‘वोट चोरी या कामचोरी’, राहुल गांधी से पूछा सवाल

रक्षा मंत्री राजनाथ ने राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि चुनावों में उसकी हार के पीछे क्या कारण रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के कथित ‘हाइड्रोजन बम’ वाले बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन आरोपों को बड़े खुलासे के रूप में पेश किया गया था, वे उनके मुताबिक प्रभावी साबित नहीं हुए। उन्होंने सामान्य मतदाताओं को फर्जी वोटर बताने के आरोपों पर भी आपत्ति जताई। रक्षा मंत्री ने चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव स्थगित करने की परंपरा का जिक्र करते हुए राजीव गांधी की मृत्यु के बाद पूरे

देश में चुनाव स्थगित किए जाने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि ऐसी स्थिति में केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया जाना चाहिए था या पूरे देश का।

रक्षा उत्पादन और भारत की वैश्विक साक्ष्य का उल्लेख

रक्षा मंत्री राजनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ने का दावा किया। उन्होंने डिजिटल लेनदेन, मुक्त व्यापार समझौते, अंतरिक्ष कार्यक्रम और रक्षा उत्पादन में हुई प्रगति का उल्लेख किया। उनके अनुसार, भारत का रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.80 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और देश रक्षा उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इन उपलब्धियों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और सत्ता हासिल करने के लिए टकराव का रास्ता अपना रहा है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई में कथित अंदरूनी खींचतान का उल्लेख करते हुए उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोग के बिना रायबरेली की सीट जीत सकती है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने की बढ़ा रही क्षमता

नई दिल्ली, (ए)। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ड्रोन से निगरानी के साथ हमला करने और दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता बढ़ा रही है। जुलाई से सितंबर के बीच जारी खरीद प्रस्तावों से पता चलता है कि सेना ड्रोन युद्ध से जुड़ी व्यवस्था मजबूत कर रही है। इनमें दूर तक निगरानी, लक्ष्य पहचानने, एफपीवी ड्रोन से हमला या पेलोड गिराने, सैनिकों को ड्रोन की ट्रेनिंग और दुश्मन ड्रोन को खोजकर नष्ट करने वाला स्किल शामिल है।

इसमें लंबी दूरी तक निगरानी, लक्ष्य पहचानने, एफपीवी ड्रोन से हमला करने या पेलोड गिराने, सैनिकों को ट्रेनिंग देने और दुश्मन के ड्रोन को नाकाम करने वाले उपकरण शामिल हैं। सेना ने हाल ही में 9 लो एल्टीट्यूड एरियल श्रेट रिसॉन्स एंड मिटिगेशन सिस्टम खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे पहले 10 इटीग्रेटेड लॉन्ग रेंज सर्विलांस ड्रोन के लिए टेंडर जारी किया गया था। सूत्रों के मुताबिक एक तरफ सेना लंबी दूरी तक निगरानी वाले ड्रोन चाहती है। वहीं कम ऊंचाई पर आने वाले हवाई खतरों से निपटने के सिस्टम भी ले रही है।



सेना ने ड्रोन्स के लिए 273 आइटम की एक फेहरीस्त जारी की है। इसमें मोटर, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोलर, कैमरा और बैटरी के साथ रिमोटली ऑपरेटेड मल्टी-पेलोड रिलीज मैकेनिज्म भी शामिल हैं। सर्विलांस ड्रोन का काम तस्वीर या वीडियो भेजना है। पेलोड रिलीज मैकेनिज्म ड्रोन को किसी वस्तु को तय जगह पर गिराने की क्षमता देता है।

रक्षा विश्लेषक ब्रिगेडियर (रि.) शरदेदु का कहना है कि ड्रोन युद्ध क्षमता का आकलन पाकिस्तान-चीन के मुकाबले करना जरूरी है। चीन

के पास ड्रोन उत्पादन, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और एआई आधारित तकनीक का मजबूत आधार है। पाक चीनी तकनीक और तुर्किये की मदद से ड्रोन क्षमता बढ़ा रहा है। भारत के सामने चुनौती सिर्फ ड्रोन लेने की नहीं, बल्कि सीमा पर निगरानी, सटीक जवाबी कार्रवाई और दुश्मन के ड्रोन हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। सेना के खरीद प्रस्तावों में ये व्यापक सोच दिखती है। चीन की क्षमता के मुकाबले के लिए स्वदेशी निर्माण, तेज मरम्मत और कम लागत में बड़ी संख्या में ड्रोन बनाने की क्षमता भी जरूरी है।

दिल्ली में धरना-प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के युवा नेताओं और कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में

नई दिल्ली, (ए)। दिल्ली में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, ईंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और कांग्रेस सेवा दल से जुड़े बीवी श्रीनिवास समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। कुछ कार्यकर्ताओं को गुरुवार देर रात और कुछ को शुक्रवार तड़के हिरासत में लिया गया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता संगठन की महिला कार्यकर्ताओं के साथ हुई बदसलुकी और मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस की एक महिला अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे थे। एनएसयूआई का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की एक महिला अधिकारी ने महिला



कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। संगठन का दावा है कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से औपचारिक शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कानूनी कार्रवाई या एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी अधिकारी के खिलाफ तत्काल

प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, तो आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर और उग्र किया जाएगा। संगठन ने साफ कहा है कि शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर न्याय की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वहीं, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए इन आरोपों और धरने को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

भारत की मिसाइलों से डरा पाकिस्तान, तैयार कर रहा तीन स्तरीय रक्षा रणनीति

नई दिल्ली, (ए)। ब्रह्मोस, स्कैल्प और रैंपेज जैसी मिसाइलों की मौजूदगी ने भारत की मारक क्षमता को मजबूत

किया है। इस चुनौती से निपटने के लिए पाकिस्तान चीन से मिले हथियारों और आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों पर निर्भरता बढ़ा रहा है। हालांकि, उसकी रई रणनीति कितनी कारगर होगी, यह वास्तविक युद्ध परिस्थितियों और दोनों देशों की तकनीकी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। भारत की स्टैंडऑफ रणनीति का उद्देश्य अपने लड़कू विमानों को दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों के सीधे निशाने से दूर रखते हुए हमला करने में सक्षम बनाना है।

भारत की इस क्षमता का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। पहली रणनीति चीन से प्राप्त एचक्यू-9पी और एचक्यू-16 जैसी वायु रक्षा प्रणालियों के जरिए अहम सैन्य ठिकानों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा मजबूत करना है।

इन प्रणालियों का उद्देश्य हवाई खतरों का पता लगाकर उन्हें रोकने की क्षमता बढ़ाना है। हालांकि, किसी मिसाइल को



रोकने की सफलता रखार की क्षमता, लक्ष्य की दूरी और परिस्थितियों समेत कई कारकों पर निर्भर करती है। दूसरी रणनीति लड़कू विमानों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को मजबूत करना है। पाकिस्तान के जे-10सीई और जेएफ-17 ब्लॉक-3 लड़कू विमानों के साथ चीन की पीएल-15ई मिसाइलें उसकी हवाई युद्ध क्षमता का हिस्सा हैं। इन

हथियारों के जरिए पाकिस्तान भारतीय विमानों को दूरी से चुनौती देने की कोशिश कर सकता है। तीसरा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और निगरानी प्रणालियों का है। हवाई निगरानी विमानों, रखर और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक के जरिए आने वाले खतरों की पहचान करने और कुछ मार्गदर्शन प्रणालियों को बाधित करने की क्षमता विकसित करना इसका उद्देश्य है। हालांकि, सभी मिसाइलों को जैमिंग से प्रभावित नहीं किया जा सकता।

पाकिस्तान की इन तैयारियों के सामने आर्थिक संसाधनों और विदेशी तकनीक पर निर्भरता जैसी चुनौतियां भी हैं। अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों के रखरखाव, प्रशिक्षण और लगातार उन्नयन पर भारी खर्च होता है। दूसरी ओर, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को जैमिंग से प्रभावित नहीं किया जा सकता। आधार पर युद्ध का परिणाम तय नहीं किया जा सकता।

राहुल ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, अपमान का सवाल ही नहीं: शिवकुमार

नई दिल्ली, (ए)। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार को लेकर उठे कथित विवाद पर सीएम डीके शिवकुमार ने सफाई दी है। उन्होंने साफ कहा है कि राहुल गांधी ने ही उन्हें सीएम बनाया है और उनके प्रति अपमान जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बीजेपी और कुछ मीडिया संस्थानों पर इसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। वहीं, बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सीएम को किनारे कर कन्नड़ लोगों का अपमान किया है।

बता दें यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर दावा किया कि राहुल गांधी ने डीके शिवकुमार को धक्का देकर किनारे कर दिया। हालांकि, शिवकुमार ने इन आरोपों को सिरों से खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन में भीड़ बहुत ज्यादा थी और राहुल गांधी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने शिवकुमार को पीछे आ रहे वाहन में बैठने के लिए कहा था।

शिवकुमार ने इस बात पर जोर दिया

कि कई मीडिया संस्थानों और बीजेपी नेताओं ने इस घटना को अपमान के तौर पर पेश करना गलत है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी और राहुल



गांधी के आशीर्वाद से मैं सीएम बना हूं। यह पूरा आशीर्वाद है और हम यहां सरकार चला रहे हैं। शिवकुमार ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान सीएम डीके शिवकुमार को धक्का देना कन्नड़ लोगों का अपमान है। रवि कुमार ने कहा कि यह घटना राहुल गांधी की अपनी ही पार्टी के सीएम के प्रति अनादर को दर्शाती है।

इस प्रकार, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

मुख्यमंत्री के दावों को बल मिला। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों और बड़ी जनसभाओं में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। परमेश्वर ने समझाया कि उस स्थान पर सुरक्षा कर्मियों की प्राथमिक जिम्मेदारी राहुल गांधी की रक्षा करना और भीड़ को उनके करीब आने से रोकना था। उन्होंने बताया कि दुर्भाग्यवश मुख्यमंत्री भी उस क्षेत्र को और बढ़ गए और भीड़ के बीच उन्हें हल्का धक्का लग गया, जो कि परिस्थितियों का परिणाम था, न कि किसी अपमानजनक इरादे का। रिपोर्ट के मुताबिक इस विवाद पर बीजेपी ने राहुल गांधी

पर निशाना साधा। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के मुख्य सचेतक और बीजेपी नेता एन रवि कुमार ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान सीएम डीके शिवकुमार को धक्का देना कन्नड़ लोगों का अपमान है। रवि कुमार ने कहा कि यह घटना राहुल गांधी की अपनी ही पार्टी के सीएम के प्रति अनादर को दर्शाती है।

इस प्रकार, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

यूनस शेख एआईएमआईएम के किसी भी पद पर नहीं थे और न ही पार्टी के सदस्य थे

मुंबई, (ए)। महाराष्ट्र के ठाणे नगर महापालिका की नवनिर्वाचित एआईएमआईएम पार्षद सहर के पिता यूनस शेख के एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने की खबर पर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस घटनाक्रम को लेकर विरोधी दलों ने तंज कसने और भगवा रंग से जोड़ने की कोशिशों के बीच एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने एक वीडियो जारी कर सच्चाई बताई और इस मामले पर विराम लगाने का प्रयास किया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वारिस पठान ने साफ किया कि यूनस शेख ने किसी राजनीतिक दल को नहीं, बल्कि एक केबल यूनिट को जॉइन किया है। यूनस शेख पिछले तीस सालों से केबल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और वे उससे संबंधित एक संस्थान का हिस्सा हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूनस शेख एआईएमआईएम के किसी भी पद पर नहीं थे और न ही वे पार्टी के आधिकारिक सदस्य थे। पठान ने यह भी बताया कि उन्होंने सहर यूनस शेख से बात की है, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि वह एआईएमआईएम की कॉर्पोरेट थीं, हैं और हमेशा रहेगीं। सहर ने पहले जीत के बाद मुंब्रा को हरा करने का दावा किया था, जिससे विवाद पैदा हुआ था। पठान ने इस मामले पर मंचे बवाल को अनावश्यक बताते हुए कहा कि भारत में यह कोई नई बात नहीं है कि एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों में होते हैं। उन्होंने कई उदाहरणों का हवाला दिया जहां पिता, बेटा और बेटे अलग-अलग दलों में सक्रिय हैं। पठान ने कहा कि यूनस शेख अपनी मनमर्जी के मालिक हैं और वह कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनका एआईएमआईएम से कोई संगठनात्मक संबंध नहीं था। एआईएमआईएम ने उन अटकलों को खारिज कर दिया, जिनमें सहर शेख के भी शिवसेना की ओर झुकाव की बात कही जा रही थी।

गुजरात में पंचायत पदाधिकारियों पर आरोप की शिकायत पर शपथपत्र जरूरी

गांधीनगर (ए)। गुजरात सरकार पंचायतों के पदाधिकारियों के खिलाफ लगाए जाने वाले आरोपों को लेकर नियमों में संशोधन करने जा रही है। नए प्रावधान के तहत पंचायत पदाधिकारियों को हटाने की मांग करते हुए शिकायत करने वाले व्यक्ति को आरोपों के समर्थन में शपथपत्र देना अनिवार्य किया जा रहा है। आरोप झूठे साबित होने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कारकोच जनता पार्टी सहित विभिन्न संगठनों के आंदोलनों और विरोध के बीच राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है, पंचायत पदाधिकारियों के खिलाफ बिना ठोस आधार के आरोप लगाने और सार्वजनिक रूप से उनकी छवि खराब करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकेगी। संशोधित व्यवस्था के अनुसार, शिकायतकर्ता को पंचायत पदाधिकारी को हटाने की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में शपथपूर्वक बयान देना होगा। आरोपों की जांच के योग्य आधार होने चाहिए। शिकायतकर्ता के पास उपलब्ध दस्तावेजों का उल्लेख भी करना होगा। हालांकि, नियमों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है, प्रत्येक आरोप के साथ दस्तावेज जमा करना या अलग से अनिवार्य साक्ष्यों की सूची देना जरूरी होगा या नहीं। नए प्रावधान का उद्देश्य निराधार शिकायतों पर अंकुश लगाना है, इससे वास्तविक शिकायतों की प्रक्रिया कितनी प्रभावित होगी। यह लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

